ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

28 December 2024

ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा बांध

संदर्भ: हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसे यारलुंग त्सांगपो बांध (Yarlung Tsangpo Dam) के नाम से जाना जायेगा। तिब्बत में जांगबो नदी पर स्थित यह परियोजना चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) का हिस्सा है। यह परियोजना भारतीय सीमा के पास स्थित है और इसमें कुल 137 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है।

बांध की क्षमता और विशेषताएं:

- इस बांध से प्रतिवर्ष 300 बिलियन किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जोकि 300 मिलियन से अधिक लोगों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।
- यह जलविद्युत परियोजना चीन की कार्बन पीकिंग (carbon peaking) और कार्बन तटस्थता (carbon neutrality) रणनीति का हिस्सा है इसलिए इसे 'हरित परियोजना' (green project) माना जा रहा है, जोकि कार्बन उत्सर्जन में कमी करने में सहायक होगी।
- जलविद्युत के अतिरिक्त, यह परियोजना आसपास के क्षेत्रों में सौर (solar) और पवन ऊर्जा (wind energy) संसाधनों के विकास को प्रोत्साहित करेगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में योगदान मिलेगा।

भारत और बांग्लादेश के लिए मुख्य चिंता:

- बांध के निर्माण ने भारत और बांग्लादेश में चिंता पैदा कर दी है क्योंकि यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जोकि इन दोनों देशों से होकर बहती है। ऐसी आशंका है कि चीन पानी के प्रवाह में हेरफेर कर सकता है, जिससे बाढ़ या पानी की कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर संघर्ष के समय। इसके अतिरिक्त, बांध का आकार और पैमाना जल संसाधनों पर चीन के नियंत्रण को बढ़ा सकता है।
- यह बांध भूकंपीय (seismically) रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जिससे परियोजना की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएँ उठी हैं। हालांकि, चीन ने दावा किया है कि परियोजना पारिस्थितिकीय सुरक्षा (ecological safety) को प्राथमिकता देती है और इसके सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनका उद्देश्य भूकंपीय और पर्यावरणीय क्षति के प्रभाव को कम करना है।

बांध का प्रभाव:

- इस परियोजना से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जिससे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र (Tibet Autonomous Region) के लिए सालाना 20 बिलियन युआन (3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की आय उत्पन्न होगी। यह परियोजना इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, व्यापार सेवाओं जैसे उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देगी और क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
- बांध के निर्माण के बाद तिब्बत में बिजली, जल संरक्षण और परिवहन बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे तिब्बत और चीन के अन्य क्षेत्रों के बीच आर्थिक तालमेल भी मजबूत होगा और तिब्बत की अर्थव्यवस्था का विकास होगा।
- यह परियोजना चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें जल संसाधन प्रबंधन भी शामिल है। इसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के एक उपाय के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर ऊर्जा सहयोग (Energy Cooperation) के संदर्भ में। यह जलविद्युत स्टेशन तिब्बत में चीन के बुनियादी ढांचे के विकास में भी रणनीतिक भूमिका निभाएगा।

ब्रह्मपुत्र नदी के बारे मे:

- कैलाश पर्वतमाला (Kailash Range) से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी अपने मार्ग में आने वाले लाखों लोगों के परिदृश्य (landscape) और आजीविका को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र:

- **बेसिन:** अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में फैला हुआ है।
- **जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area):**
  - तिब्बत (2,93,000 वर्ग किमी)
  - भारत और भूटान (2,40,000 वर्ग किमी)
  - बांग्लादेश (47,000 वर्ग किमी)
  - कुल बेसिन क्षेत्र: 5,80,000 वर्ग किमी
- **डेल्टा:** यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है।

डाकघर नियम, 2024 और डाकघर विनियम, 2024

सन्दर्भ: हाल ही में डाक विभाग (डीओपी) ने डाकघर अधिनियम, 2023

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

के तहत डाकघर नियम, 2024 और डाकघर विनियम, 2024 पेश किए हैं, जोकि 16 दिसंबर, 2024 से लागू होंगे। इन सुधारों का उद्देश्य पूरे देश में डाक सेवाओं का आधुनिकीकरण और सुव्यवस्थित करना है।

डाकघर नियम, 2024 की मुख्य विशेषताएँ:

- डाकघर नियम, 2024 डाक सेवाओं के संचालन को सरल बनाते हैं, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों संस्थाओं के सहयोग से दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करना संभव हो जाता है। ये नियम डिजिटल पता पहचानकर्ता और डाक के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसी भविष्य की अवधारणाओं को पेश करते हैं, जिससे सेवा को और अधिक आसान बनाने में मदद मिलती है।

डाकघर विनियम, 2024 के बारे में:

- डाकघर विनियम, 2024 डाक सेवाओं और उत्पादों के संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। वे मेल और पार्सल को एक ही तरह के उत्पादों में रखते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के पुस्तक पैकेटों को एक ही श्रेणी ष्बुक पोस्टष् में शामिल करना। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत मनी ऑर्डर की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है।

भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 के बारे में:

- भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 एक विधायी अद्यतन है, जिसने 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम का स्थान लिया है। इस नए कानून का उद्देश्य डाक सेवाओं, नागरिक सेवाओं, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुव्यवस्थित करना है, ताकि परिचालन में अधिक दक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित हो सके।

डाकघर अधिनियम 2023 के प्रमुख प्रावधान:

- **डाक टिकट जारी करना:** भारतीय डाक को डाक टिकट जारी करने का विशेष अधिकार है।
- **सेवाएँ:** भारतीय डाक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवाएँ प्रदान करेगा।
- **अवरोधन (interception) का अधिकार:** प्राधिकृत अधिकारी राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों जैसे कारणों से डाक सामग्री को रोक सकते हैं।
- **पार्सल परीक्षण:** यदि संदेह हो, तो डाक सामग्री की जांच की जा सकती है या उसे सीमा शुल्क या किसी अन्य निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जा सकता है।
- **निजी कूरियर सेवाओं का विनियमन:** पहली बार, अधिनियम अपने ढाँचे के भीतर निजी कूरियर सेवाओं को विनियमित करता है।
- **दायित्व से छूट:** अधिनियम डाकघर को हानि, देरी या क्षति के लिए दायित्व से छूट देता है, जब तक कि सरकारी नियमों द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए।
- **अवैतनिक शुल्क की वसूली:** अवैतनिक डाक शुल्क को भू-राजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता है।
- **महानिदेशक की नियुक्ति:** डाक सेवाओं की देखरेख और संबंधित नियम बनाने के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) अनुपात

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित संपतियो (NPA) अनुपात सितंबर 2024 के अंत तक घटकर 2.5% रह गया, जोकि पिछले 13 वर्षों में सबसे कम स्तर है। यह मार्च 2024 के अंत में दर्ज 2.7% के सकल NPA अनुपात की तुलना में और अधिक सुधार को दर्शाता है।

सकल एनपीए अनुपात और शुद्ध एनपीए क्या है?

- सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (GNPA) अनुपात बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है, जोकि सहमत शर्तों के अनुसार चुकाए नहीं जा रहे हैं। इन ऋणों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि उधारकर्ता एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 90 दिन या उससे अधिक समय तक मूलधन या ब्याज चुकाने में असमर्थ रहते हैं।
- शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियाँ (NNPA) उन गैर-निष्पादित आस्तियों का हिस्सा होती हैं, जोकि खराब ऋणों के लिए बैंकों द्वारा बनाए गए प्रावधानों (आरक्षित राशि) को घटाने के बाद शेष रहती हैं। मार्च 2024 के अंत में, NNPA अनुपात घटकर 0.62% हो गया था और सितंबर 2024 तक इसमें और सुधार होकर यह 0.57% हो गया।

सकल एनपीए अनुपात में सुधार का कारण:

- सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) अनुपात में गिरावट का कारण बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality), मजबूत वसूली और पहले गैर-निष्पादित (Non-Performing) माने गए ऋणों का उन्नयन

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

(upgradation) है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों की समग्र बैलेंस शीट (Balance Sheet) निरंतर ऋण और जमा (Deposits) के विस्तार के साथ मजबूत बनी हुई है।

किस सेक्टर में सबसे ज्यादा और सबसे कम सकल NPA अनुपात है?

- सितंबर 2024 के अंत में, कृषि क्षेत्र का सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) अनुपात सबसे अधिक 6.2% था, जबकि खुदरा ऋण क्षेत्र में यह सबसे कम 1.2% दर्ज किया गया। शिक्षा ऋणों के GNPA अनुपात में मार्च 2023 में 5.8% से घटकर सितंबर 2024 तक 2.7% तक की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई।

स्लिपेज अनुपात क्या है?

- स्लिपेज अनुपात (Slippage Ratio) उस दर को मापता है, जिस पर वर्ष की शुरुआत में मानक अग्रिम (standard advances) एनपीए (NPA) में बदल जाते हैं। यह दिखाता है कि एक निश्चित अवधि में कितने ऋण खराब हो रहे हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के दौरान स्लिपेज अनुपात में सुधार हुआ है।

बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में किस तरह सुधार हुआ है?

- बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जोकि सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) और शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियों (NNPA) अनुपात में कमी से स्पष्ट है। कुल अग्रिमों में मानक परिसंपत्तियों (standard assets) का हिस्सा बढ़ा है, जबकि गैर-मानक अग्रिमों में गिरावट बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन का संकेत देती है।
- विभिन्न ऋण श्रेणियों में GNPA अनुपात में सुधार दर्ज किया गया है, विशेष रूप से शिक्षा ऋणों में, जहां यह अनुपात मार्च 2023 में 5.8% से घटकर सितंबर 2024 तक 2.7% हो गया। इसी तरह, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (consumer durables) जैसे खुदरा ऋणों में भी एनपीए (NPA) में कमी दर्ज की गई।

एनपीए में गिरावट का महत्व:

- एनपीए में गिरावट यह दर्शाती है कि बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे लाभप्रदता (profitability) और स्थिरता (stability) बढ़ रही है। इससे बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं (depositors) और निवेशकों (investors) का विश्वास भी मजबूत होता है।
- कम GNPA अनुपात सामान्यतौर पर बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता (asset quality) और अधिक कुशल बैंकिंग संचालन (efficient banking operations) का संकेत देता है।
- यह दिखाता है कि बैंक अपने क्रेडिट जोखिम (credit risk) को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहे हैं, जिससे चूक (defaults) कम हो रही है और प्रावधान (provisions) की आवश्यकता घट रही है। इससे बैंकों की वित्तीय ताकत में सुधार हो रहा है।

सकल एनपीए अनुपात की तुलना:

कुछ वर्षों के सकल एनपीए (Gross NPA) अनुपात की तुलना:

- 2010-11: 2.35%
- 2015-16: 7.48%
- 2020-21: 7.33%
- 2023-24: 2.7%
- 2024-25 (सितंबर 2024): 2.5%

संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट

सन्दर्भ: हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 के लिए 3.72 बिलियन डॉलर के नियमित बजट को मंजूरी दी है, जोकि महासचिव द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्रस्ताव से 1 मिलियन डॉलर अधिक है। यह बजट स्वीकृति एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र को अपने सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाएगी।

- इसके अतिरिक्त, महासभा ने 2024-2034 के दशक के लिए भूमिबद्ध विकासशील देशों (Landlocked Developing Countries- LLDCs) के लिए कार्य योजना को भी अपनाया। इस योजना का उद्देश्य LLDCs की विशिष्ट विकास चुनौतियों, जैसे सीमित बाजार पहुंच, उच्च परिवहन लागत और आर्थिक विविधीकरण की कमी को संबोधित करना है।

क्या यह बजट संयुक्त राष्ट्र के लिए एकमात्र वित्तीय आवंटन है?

- नहीं, यह बजट केवल नियमित बजट (Regular Budget - RB) के लिए है, जोकि कैलेंडर वर्ष चक्र (1 जनवरी से 31 दिसंबर) पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र के पास शांति अभियानों (Peacekeeping Operations) के लिए एक अलग बजट भी है, जोकि वित्तीय वर्ष चक्र (1 जुलाई से 30 जून) का अनुसरण करता है।

संयुक्त राष्ट्र के बारे में:

- संयुक्त राष्ट्र (UN) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1945 में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, शांति और सुरक्षा बनाए रखने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। इसके अतिरिक्त, होली सी (Holy See) और फिलिस्तीन (Palestine) पर्यवेक्षक देश हैं।

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य:

- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना।
- मानव अधिकारों (Human Rights) और मौलिक स्वतंत्रता (Fundamental Freedoms) के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना।
- आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- राष्ट्रों की गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना।

संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए जिम्मेदार प्रमुख घटनाएँ:

- **1920:** प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ (League of Nations) का गठन।
- **1941:** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अटलांटिक चार्टर (Atlantic Charter) पर हस्ताक्षर, जिसमें युद्धोत्तर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का आह्वान किया गया।
- **1945:** 26 जून को 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर (UN Charter) पर हस्ताक्षर, जिसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक गठन हुआ।

संयुक्त राष्ट्र का संगठनात्मक ढांचा:

संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंग हैं:

- महासभा (United Nations General Assembly - UNGA)
- सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council -UNSC)
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice - ICJ)
- सचिवालय (Secretariat)
- आर्थिक और सामाजिक परिषद (Economic and Social Council - ECOSOC)
- ट्रस्टीशिप काउंसिल (Trusteeship Council) – 1994 से निष्क्रिय
- इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूनिसेफ (UNICEF) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) जैसी विशिष्ट एजेंसियों, निधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करता है।

पॉवर पैक्ड न्यूज

एम.टी. वासुदेवन नायर: मलयालम साहित्य और सिनेमा का सितारा

- प्रसिद्ध मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता एम.टी. वासुदेवन नायर का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- एम.टी. के नाम से लोकप्रिय वासुदेवन नायर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे न केवल एक महान लेखक थे, बल्कि एक प्रशंसित फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक भी थे। उनके तीन मौलिक उपन्यास –नालुकेट्टु, असुरविथु और कालम मलयालम साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं।
- उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण शामिल हैं। साहित्य जगत में उनके योगदान को केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, वायलर पुरस्कार, और वल्लथोल पुरस्कार जैसे सम्मानों से भी सराहा गया।
- फिल्मी दुनिया में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनकी पटकथाओं और निर्देशित फिल्मों ने मलयालम सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 2022 में उन्हें केरल सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- एम.टी. वासुदेवन नायर की रचनाएं मातृसत्तात्मक समाज की जटिलताओं और सामाजिक मुद्दों पर गहरी दृष्टि प्रस्तुत करती हैं। उनके निधन से साहित्य और सिनेमा जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है।

बाल्ड ईगल: अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी

- 250 वर्षों के बाद, बाल्ड ईगल को अमेरिका का आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह गौरवशाली पक्षी वर्षों से अमेरिकी शक्ति, साहस, स्वतंत्रता और अमरता का प्रतीक रहा है। बाल्ड ईगल को 1940 के राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया, जिससे इसका शिकार या व्यापार करना अवैध हो गया।
- यह पक्षी एक समय विलुप्ति के कगार पर था, लेकिन संरक्षण प्रयासों और कानूनों की बदौलत 2009 के बाद से इसकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
- बाल्ड ईगल उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है और इसे आधिकारिक दस्तावेजों, संधियों और आयोगों में राष्ट्रीय

प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

- इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण बाल्ड ईगल ने हमेशा अमेरिकी जनता के दिलों में खास जगह बनाई है। इसकी विशाल पंखों की उड़ान और निर्भीक व्यक्तित्व इसे शक्ति और स्वतंत्रता का आदर्श बनाते हैं। आज, बाल्ड ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि अमेरिकी इतिहास और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।

एसएलआईएनईएक्स 24: भारत-श्रीलंका नौसेना अभ्यास

- भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास एसएलआईएनईएक्स 24 17 से 20 दिसंबर 2024 के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। यह अभ्यास दो चरणों में संपन्न हुआ: 17-18 दिसंबर को बंदरगाह चरण और 19-20 दिसंबर को समुद्री चरण।
- इस अभ्यास में भारत की ओर से आईएनएस सुमित्रा और श्रीलंका की ओर से एसएलएनएस सयूरा ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह 17 दिसंबर को आयोजित हुआ और समुद्री अभ्यास 19 दिसंबर को शुरू हुआ।
- एसएलआईएनईएक्स श्रृंखला की शुरुआत 2005 में हुई थी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास पूर्वी नौसेना कमान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें नौसैनिक युद्ध कौशल, संचार और तालमेल को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
- यह अभ्यास दोनों देशों की रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करता है और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान देता है। एसएलआईएनईएक्स 24 ने भारत और श्रीलंका के बीच रणनीतिक संबंधों को और अधिक गहरा किया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी: 100 वर्षों का गौरवशाली इतिहास

- 26 दिसंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए। इसका गठन दिसंबर 1925 में कानपुर में सिंगारवेलु चेट्टियर के नेतृत्व में हुआ। यह पार्टी 1917 की रूसी क्रांति और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष से प्रेरित थी।
- सीपीआई के गठन में एम.एन. रॉय और अबानी मुखर्जी जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखकर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव रखी।
- स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सीपीआई ने श्रमिकों और किसानों के आंदोलनों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। अखिल भारतीय किसान सभा जैसे संगठनों के माध्यम से पार्टी ने किसानों के अधिकारों की वकालत की।
- आज, 100 वर्षों बाद भी सीपीआई का योगदान भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में अमूल्य है। यह पार्टी न केवल स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का प्रतीक भी बनी हुई है।

पंजाब में 100 प्रतिशत पाइप जलापूर्ति

- पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला भारत का पांचवा राज्य बन गया है। यह उपलब्धि केंद्र सरकार की 'हर घर जल' योजना के तहत हासिल की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में साफ पानी की पहुंच सुनिश्चित करना है।
- पंजाब में पानी की गुणवत्ता और कमी की समस्या को दूर करने के लिए 2174 करोड़ रुपये की लागत से 15 बड़ी जल परियोजनाएं चल रही हैं। इनसे 1706 गांवों के लगभग 25 लाख लोगों और 4 लाख परिवारों को फायदा होगा।
- इसके साथ ही, राज्य के सभी गांव खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं। पंजाब में 10435 से अधिक गांव अब ओडीएफ प्लस (वांछनीय) बन चुके हैं, जबकि 1289 गांवों ने ओडीएफ प्लस (आदर्श) का दर्जा हासिल कर लिया है।
- यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और जीवन स्तर सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।